



Neutral Citation No. – 2026:AHC:127782

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19421 सन् 2026

नफ़ीस और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: राहुल सिंह दहिया

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और उ0प्र0 राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 02 सन् 2026 धारा 115(2), 80(2), 85 बीएनएस एवं धारा 3 और 4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना- औरंगाबाद, ज़िला- बुलंदशहर में आवेदकों की ज़मानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक संख्या 1 मृतका के ससुर हैं, जबकि आवेदक संख्या 2 सास हैं। आवेदकों पर केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदकों के बेटे और मृतका की शादी 19.06.2020 को हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 24.12.2025 को हुई थी, जबकि एफआईआर 01.01.2026 को दर्ज की गई थी, और अभियोजन पक्ष ने इतनी देरी का कोई कारण नहीं बताया है। आवेदक मृतका और उसके पति से अलग रह रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट है और उनका विसरा सुरक्षित रखा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। अभियोजन पक्ष को विसरा रिपोर्ट नहीं मिली है। आगे यह भी कहा गया है कि मृतका की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया है कि वे 29.01.2026 से जेल में बंद हैं और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों को जमानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि अपराध में शामिल होने के संबंध में आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदकों द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदकों ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **नफीस** और **श्रीमती नसीम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेंगे कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदकों को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उनके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो परीक्षण न्यायालय उनके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करना। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।